important. The recommendations call for a very detailed accounting process and actuarial exercise and any kind of mismatch between the fund management and the investment returns and the liability will need to be met by the Government. Now, the proposed pension scheme, in view of the structure, in view of the manner and in view of meeting the pension liabilities, will have huge ramifications. The ramifications are very big, and they have very far reaching implications. They require very detailed examination and they also require extensive inter-ministerial consultations. The process of this consultation has already been initiated and a view on this will be taken very quickly.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Do you think it will take six months or more?

SHRIMATI VASUNDHARA RAJE: The Finance Ministry has to come back to us with a detailed report, every Ministry has to come back with a detailed report. And we have sent reminders. We will be waiting for all the information to come back, before we can formulate the scheme.

THE DEPUTY CHAIRMAN: She has given such an extensive answer. Question No. 147.... (*Interruptions*)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: So, no further supplementary questions?

THE DEPUTY CHAIRMAN: She has given all the answers to the supplementary questions. Question No. 147.

Strengthening of PDS infrastructure

*147. SHRI LAJPAT RAI: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that for the purpose of strengthening PDS infrastructure, trucks/vans are also provided to make available essential commodities in rural/hilly remote areas;

(b) whether Government subsidise the cost of such vehicles;

(c) if so, the amount paid during the last three years; and

(d) the number of such trucks/vans and in whose custody Centre/ State/Union Territory Governments these vehicles are being maintained?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD YADAV): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

(a) and (b) Yes, Sir. Under the Centrally Sponsored Scheme "Purchase of Mobile Vans/Trucks", financial assistance, comprising 50% loan and 50% subsidy, was provided to State Governments/Union Territories for strengthening of the Public Distribution System infrastructure, especially in the remote, hilly, rural and tribal areas of the country. The scheme has been discontinued with effect from 1.4. 2002 *i.e.* from the commencement of the 10th Plan.

(c) and (d) The amounts released during the last 3 years and the number of vehicles sanctioned are given below:

Year	No. of trucks/vans sanctioned	Amount released (Rs. in lakhs)
1999-2000	9	106.27
2000-2001	20	98.93
2001-2002	4	30.00
TOTAL:	33	235.20

The vehicles are in the custody of the Sate Governments/Union Territories Administrations and are maintained by them.

लाला लाजपत राय: उपसभापति महोदया, जो जवाब लिखा गया है, वह मैंने पढ़ा है और उस जवाब में से मेरी कुछ जानकारी लेने की इच्छा है। सबसे पहले मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि गाड़ियों को सब्सिडाइज करने की जो स्कीम चालू थी, उसको 01-04-2002 से बंद कर दिया गया है, तो क्या आपने यह संबंधित मंत्रालय के मश्वरे के हिसाब से किया है या कोई और रिपोर्ट है या स्वयं ही कर दिया गया है? अगर ऐसा है तो उसका नतीजा क्या होगा? गाड़ियां तो खराब होंगी ही होंगी, तो जिस काम के लिए गाड़ियां ली गई थीं उसकी जगह क्या और कोई बंदोबस्त होगा?

अपने प्रश्न के (बी) भाग के रूप में मैं यह जानना चाहता हूं कि इन गाड़ियों की मेंटेनेंस का क्या बंदोबस्त है, क्या उन स्टेट्स से कोई समाचार है? ये 33 गाड़ियां हैं, क्या ये 33 की 33 गाड़ियां चलती हैं या नहीं और क्या इनकी मेंटेनेंस का बंदोबस्त ठीक है?

श्री शरद यादव: उपसभापति महोदया, लाला जी ने सवाल किया है कि इस स्कीम की क्या हालत है, इस बारे में मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि प्लानिंग कमीशन द्वारा...

उपसभापति: आप जरा जोर से बोलेंगे, आवाज नहीं आ रही।

श्री शरद यादव: 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस स्कीम को बंद करने के लिए कहा गया है। इसके पीछे कारण थे कि सीएजी से लेकर हमारा और सबका ऐक्सपीरिएंस था कि इसमें 1569 व्हीकल्स पर पूरे देश में करीब 65 करोड़ रुपया सरकार का गया, लेकिन इस स्कीम में यह देखा गया कि हमने जो पैसा दिया, जो व्हीकल्स लिए गए, वे जिस मकसद से लिए गए थे, हिली एरियाज़ के लिए, उनमें उनका कोई इस्तेमाल नहीं होता। उस पैसे को डाइवर्ट भी किया जाता है, उस पैसे से जो व्हीकल्स लिए जाते हैं, उनको दूसरे कामों में लगाया जाता है और इन सारी चीजों को देखकर सीएजी ने भी और प्लानिंग कमीशन ने भी कहा कि यह स्कीम वायबल नहीं है और इस स्कीम को बंद करके इसकी जगह जो हिली एरियाज़ हैं, जो बर्फ वाले इलाके हैं, उनमें 50 किलोमीटर के बियांड उन्हें हम किराया सब्सिडाइज़ करते हैं। तो हिली एरियाज़ के लिए हमने जो यह स्कीम चलाई थी, वह पूरी तरह से सफल नहीं है और लाला जी जब व्हीकल्स का सवाल उठा रहे हैं तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि ये व्हीकल्स स्टेट गवर्नमेंट्स के पास हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं लेकिन इन व्हीकल्स की हालत अच्छी नहीं है, परन्तु ये सब स्टेट गवर्नमेंट् के पास हैं और यह स्कीम जिस मकसद से चलाई गई थी, उस मकसद को यह पूरा करने में कामयाब नहीं हुई। उसकी बनिस्बत, उसकी जगह जो हिली एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ में हम लोग ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी दे रहे हैं, बर्फ वाले इलाकों में ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी देने का काम हम कर रहे हैं और इसमें ज्यादा सुविधा हो रही है तथा यह ज्यादा कारगर है।

लाला लाजपत राय: महोदया, मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का माननीय मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया। आपने जो कुछ कहा है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं कि मंत्री जी को इस बात की जानकारी कब प्राप्त हुई कि इसका पैसा डाइवर्ट होता है? अगर पहले साल में जानकारी हुई तो एकदम इन्होंने इसे बंद क्यों नहीं किया? यह तीन साल लगातार चलता रहा, तो यह डाइवर्ज़न कब हुआ, मैं यह जानना चाहता हूं?

इसके साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या आपके पास इन गाड़ियों के इस्तेमाल के बारे में कोई रिपोर्ट है, कोई लॉग बुक के बारे में कोई खबर है कि गाड़ियां चलती हैं या नहीं चलती हैं?

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि 33 गाड़ियां खरीदी गईं। पहले साल में 9 गाड़ियां खरीदी गईं 1.6 करोड़ में, दूसरे साल में 20 गाड़ियां खरीदी गईं 98.93 लाख में और अगले साल

में 4 गाड़ियां खरीदी गईं 30 लाख में, इनके अंदर कीमत का प्रपोशन कोई नहीं है। कहीं गाड़ी 7.5 लाख की है, कहीं 4 लाख की है, कहीं 12 लाख की है, मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या हिसाब है? तरह-तरह की गाड़ियां ली गईं, तरह तरह की गाड़ियां लेने का क्या कारण है? तरह-तरह की गाड़ियों की देख-रेख में बहुत मुश्किल आती है, अगर एक मेक की गाड़ी ली जाए तो उसकी देख-रेख में आसानी होती है। मेरी समझ में नहीं आया कि ये रंग-बिरंगी गाड़ियां क्यों ली गईं? मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस बारे में रोशनी डालें।

श्री शरद यादव: महोदया, लाला जी खुद ही अपने सवाल का जवाब दे रहे हैं। सीधी बात है कि ... (व्यवधान)

उपसभापति: आपकी जगह तो नहीं ले रहे हैं ना?

श्री शरद यादव: नहीं, उन्होंने हमारी जगह ले ली है, इस सवाल का जवाब उन्होंने दे दिया है। मैं इस स्कीम की दुर्गति बताता हूं जो लाला जी ने खुद पढ़कर बताई है। महोदया, 1999-2000 में 10 करोड़ रुपए हमने इसके लिए बजट में दिए थे। उसमें से जो उठान हुआ, वह 0.06 करोड़ रुपए का हुआ। दूसरे साल यानी 2000-2001 में 98 लाख रुपए का उठान हुआ। फिर तीसरे साल यानी 2001-2002 में 30 लाख रुपए का उठान हुआ। यानी इस स्कीम में पैसे का उठान नहीं हो रहा है। हम पैसा एलॉट कर रहे हैं लेकिन ये लोग केवल 30 लाख रुपए उठा पाए। दूसरी बात यह है कि व्हाईकल्स जो खराब है, उसे सीएजी ने देखा, हमारे डिपार्टमेंट ने इसे सुपरवाईज़ किया, इन सारे अनुभवों को मिलाकर यह देखा गया कि इस स्कीम में पैसा बरबाद हो रहा है और इसमें 60-65 करोड़ रुपया बरबाद हो चुका है। इन 3 सालों के हालात हमने देखे तो पाया कि सूबों की सरकारें भी इसमें रुचि नहीं रखती हैं कि इस पैसे को उठाएं। हमने इसे फिफ्टी-फिफ्टी कर दिया यानी लोन और सब्सिडी का, तब भी लोग इसे उठाने को तैयार नहीं हैं। इसकी जानकारी सीएजी ने हमें दी और प्लानिंग कमीशन ने भी कहा कि यह स्कीम ठीक नहीं है। हमारे विभाग ने सब जगह देखा कि इसका काम ठीक तरह से नहीं चल रहा है। फिर यह 3 साल का जो अनुभव है कि रुपया हमारे पास है लेकिन सरकारें इसमें रुचि नहीं रखती हैं। इसलिए इस स्कीम को बंद किया गया है और यह वाजिब है।

श्री दत्ता मेघे: महोदया, मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि शरद यादव जी ने कहा कि सरकारें इसमें रुचि नहीं रखतीं, इसलिए यह स्कीम बंद कर दी। जब यह स्कीम चालू थी, तब मैं महाराष्ट्र में सिविल सप्लाईज़ डिपार्टमेंट का मिनिस्टर था। महाराष्ट्र में यह स्कीम बहुत अच्छी चली। हमारा मेघाठा, जो आदिवासी ऐरिया है, जहां कुपोषण के कारण बहुत बच्चे मर रहे थे, वहां हमने यह स्कीम चलाई और इसका फायदा हुआ। महाराष्ट्र ने यह स्कीम बहुत अच्छी चलाई थी। हमारा

जो आदिवासी ऐरिया है चन्द्रपुर का, वहां यह स्कीम बहुत अच्छी चली थी और आप कह रहे हैं कि आपने स्कीम बंद कर दी। मुझे यह समझ में नहीं आया कि इतनी अच्छी स्कीम का सर्वे आपने नहीं किया और एक अच्छी स्कीम को आपने बंद कर दिया। हमारे महाराष्ट्र में मेघाठ में लोग मरते थे, उस गांव में लोग दुकान से राशन लेकर नहीं जा सकते थे, वहां के लिए यह एक अच्छी स्कीम थी। एक अच्छी स्कीम बंद करके उसका जस्टिफिकेशन शरद यादव सरीखे मंत्री जी कर रहे हैं, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इसे इंप्लीमेंट किया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जो कुपोषण हो रहा है, क्या उसको रोकने के लिए मंत्री जी इस स्कीम पर पुनर्विचार करेंगे और क्या इसे फिर से शुरू करेंगे?

श्री शरद यादव: महोदया, यह स्कीम काफी दिनों से चली हुई है। जब दत्ता मेघे वहां रहे होंगे तो बेशक यह स्कीम अच्छी चली होगी। मैं आपके सूबे की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने यह नहीं कहा है कि यह स्कीम सब जगह फेल हो गई है। कुछ जगह जैसे दक्षिण भारत के जो इलाके हैं, वहां हर स्कीम ठीक चलती है। लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट पालिसी बनाती है तो केवल एक सूबे के लिए नहीं बना सकती है। महोदया, मेरा इस बात में कोई डिस्प्युट नहीं है कि इनके जमाने में यह स्कीम चली होगी लेकिन मैंने जो आंकड़े पढ़े हैं, उनमें महाराष्ट्र भी शामिल है कि वहां कितना पैसा उठाया गया है, यानी लोगों की इसमें कितनी रुचि है। मैंने यह कहा कि इसमें लोगों की रुचि नहीं है। मैं मानता हूं कि यह स्कीम आपके जमाने में अच्छी चली होगी। आप प्रबंध करने में उस्ताद हैं, यह मैं अच्छी तरह जानता हूं, आपने जरूर अच्छा इंतजाम किया होगा, जहां अच्छा आदमी होगा वह जरूर अच्छा इंतजाम करेगा लेकिन ओवरऑल पूरे देश भर के लिए यह स्कीम है और उसमें सारी चीजों को देखकर ही हमने यह फैसला किया है। यह फैसला हमने अकेले नहीं किया, बल्कि सी.ए.जी. ने रिपोर्ट दी है कि बड़े पैमाने पर इसका मिसयूज़ हो रहा है और सही परपज़ के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मैं मानता हूं कि यह सब जगह नहीं हुआ, कुछ जगह ठीक भी हुआ है।

उपसभापति: जहां ठीक हुआ है, वहां क्यों बंद कर रहे हो? जहां ठीक नहीं हुआ है, वहां बंद करिए।

श्री शरद यादव: मैडम, स्कीम तो सबके लिए एक सी होगी ना।

उपसभापति: यानी जो अच्छा काम कर रहे हैं वे भी suffer करेंगे ....(**व्यवधान**)

श्री शरद यादव: महोदया, आपका इंप्रेशन ठीक नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमने यह स्कीम बंद नहीं की है। जहां डिपो से 50 किलोमीटर आगे है, उसमें जो हिली ऐरियाज़ हैं ... (**व्यवधान**)

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Madam, please come to our rescue. Why should he stop the scheme in the States which are doing well? Instead, he should fund the scheme in the States which are doing well. ...(*interruptions*)..

उपसभापति: जो स्टेट अच्छा काम कर रहे हैं उनको देंगे और जो खराब काम कर रहे हैं उनको नहीं देंगे तो खराब काम करने वाले भी अच्छे हो जाएंगे। ...(**व्यवधान**)

श्री सुरेश कलमाडी: इस पर हाफ-इन-ऑवर डिस्कशन होना चाहिए।

श्री शरद यादव: यह कोई हाफ-इन-ऑवर वाला मामला नहीं है।

डा॰ अलादी पी॰ राजकुमार: मैडम, लकिली प्रधान मंत्री जी भी यहां मौजूद हैं। मैं प्रधान मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि देश में जो स्टेट अच्छा काम कर रही है उन स्कीमों को वहां कायम रखा जाए। इस ओर मैं प्रधान मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। प्रधान मंत्री जी, जो स्कीम साउथ इंडिया में काफी अच्छी चल रही है उनको बंद करने के लिए यहां मंत्री जी ने ऐलान किया है। ...(**व्यवधान**) मैडम, मैं आपकी अनुमति से प्रधान मंत्री महोदय से कह रहा हूं। दक्षिण भारत में यह स्कीम अच्छी चल रही हैं, यह इनको बंद करना चाह रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस स्कीम को रिवाइव किया जाए।

श्री शरद यादव: मैडम, मैंने यह बात नहीं कही। कुछ स्कीमों के बारे में साउथ में परफार्मेंस बैटर है। ......(**व्यवधान**) महोदया, मैं आपके सामने पूरा पढ़ कर बतला देता हूं।

श्री रूमान्डला रामचन्द्रय्या: पूरे देश में अच्छा चल रहा है।

उपसभापति: बैठिए-बैठिए।

श्री शरद यादव: मेरे पास पूरे आंकड़े हैं। ....(**व्यवधान**) जो अच्छी स्कीम हैं हमने उनको बंद नहीं किया है। 50 किलोमीटर के ऊपर हम सब्सिडी दे रहे हैं।

श्री रूमान्डला रामचन्द्रय्या: जवाब मत बदलिए।

उपसभापति: जो जवाब उन्होंने दिया है वह रिकार्ड पर रहेगा। It is an assurance that he has given to you. Why do you object to it? Question Hour is over.